Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 16 , 07 अक्टुबर, शनिवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक 9879141480 4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

जेईई एडवांस्डः 4 हजार से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे

कानपुर। आईआईटी में दाखिले का सपना संजोने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस्ड में इस साल चार हजार से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। जेईई मेंस के टॉप 2,24,000 रैंक वाले छात्र-छात्राएं जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह जानकारी जेईई एडवांस्ड के चेयरमैन प्रो. शलभ ने दी। उन्होंने बताया कि अभी तक जेईई एडवांस्ड में जेईई मेंस के टॉप 2,20,000 रैंक वाले छात्र-छात्राएं ही आवेदन कर सकते थे। इस बार चार हजार अधिक छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिल सकेगा। सत्र 2018 में जेईई एडवांस्ड आईआईटी कानपुर आयोजित कर रहा है। जेईई एडवांस्ड 2018 की परीक्षा 20 मई को दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह नौ से 12 तो दूसरी पाली दोपहर दो से शाम पांच बजे के बीच होगी।

कलस्टर पार्किंग नीति ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की ''नीति'

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्लस्टर पार्किंग पॉलिसी के तहत ठेके की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जिन तीन पार्किंग स्थल को क्लस्टर के साथ जोड़कर निविदा जारी की गई है उससे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली निगम की बेहतर आर्थिक स्थिति को करारा झटका लगने का अनुमान है। नगर निगम की आय का प्रमुख जरिया आरपी सेल यानी विज्ञापन और पार्किंग है। इसके अलावा हाउस टैक्स से भी निगम को फायदा होता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत 104 पार्किंग स्थल है। 6 मल्टीलेवल पार्किंग हैं। 30 पार्किंग बनाने को जगह चिह्नित की गई है। पार्किंग से करीब 60 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती रही है। बहरहाल नगर निगम के गठन के बाद नए तरीके से पार्किंग को ठेके पर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए क्लस्टर पार्किंग नीति बनाई गई है। इस पार्किंग नीति के तहत हाल ही में तीन क्लस्टर पार्किंग के लिए निविदा जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अगस्त को पार्किंग के लिए टेंडर निकाला गया।

महिला व कारोबारी से ठगी, मामला दर्ज

नई दिल्ली। पुल प्रहलादपुर तथा लाजपतनगर इलाके में एक महिला तथा एक कारोबारी से ठगी की गई। पुलिस ने दोनो मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली है लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मूलरूप से ककरोला मानेसर निवासी श्यामा देवी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं। 3 अक्टूबर को वह मानेसर से तेहखंड गांव निवासी अपने दामाद से मिलने आई थीं। वह महरौली-बदरपुर रोड पर ओखला मोड़ के पास बस आने का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान दो लोग महिला के पास पहुंचे और उन लोगों ने महिला को कपड़े में बंधी हुई नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा कि इसमें एक लाख रुपए हैं। यह रकम उनके ठेकेदार की है। वे इसे चुराकर लाए हैं। इसके बदलने उन लोगों ने महिला से कानों के दोनों कुंडल, सोने की अंगूठी और 4,000 रु पये लेकर चंपत हो गए। एक अन्य मामले में लाजपत नगर इलाके में यह ठगी अनुज वर्मा से हुई। उन्होंने बताया कि वह दूध सप्लाई करते हैं। मंगलवार दोपहर को वह 1.65 लाख रुपए लेकर लाजपत नगर स्थित एक बैंक में जमा कराने गए थे। बैंक में कैश जमा कराने को जब वह फॉर्म भर रहे थे। इस दौरान दो लोग उनके पास पहुंचे। दोनों लोग फॉर्म भरने की बात करते हुए उन्हें बैंक से बाहर गोल चक्कर के पास ले गए। जहां उन्होंने पीड़ित को रूमाल में बंधी नोटों की गड्डी देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। पीड़ित का बयान है कि इस दौरान उसने अपनी जेब से 70 हजार रुपए निकाल ठगों को दिया। कोशिश कर रही है।

बेटी की थी शादी, हो गई घर में चोरी

नई दिल्ली। सागरपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के घर चोरी हो गई। शातिर चोर पीड़ित के घर से जेवरात नकदी तथा कपड़े आदि चुरा ले गए। इस बाबत प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सागरपुर के दशरथपुरी में देवनारायण झा परिवार के साथ रहते हैं उनके परिवार में तीन बेटियां व एक बेटा है। इनमें से बड़ी बेटी की शादी नवम्बर माह में होने वाली थी।

सार्वजनिक होंगे कोलेजियम के फैसले

अब उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति के बारे में जानेगी जनता

नई दिल्ली। न्यायिक नियुक्तियों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम खुलेपन की राह पर चल पड़ा है। सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने ऐतिहासिक फैसले किया है कि कोलेजियम की सभी कार्यवाही सार्वजनिक की जाएगी और उसे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के लगभग 64 वर्षों के इतिहास में पहला मौका है जब जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया गया है।

कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों को चयन मंडल होता है जो उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति करता है। इस फैसले के लिए सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर 'कोलेजियम रिजोल्यूशन' नाम से अगल लिंक सृजित किया गया है। कोलेजियम का काम हाईकोर्ट में जजों का स्थानांतरण, प्रोन्नति और सुप्रीम कोर्ट में जजों की प्रोन्नति करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रम में 3 अक्तूबर को लिए विचारित गए केरल और मद्रास हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के तीन प्रस्ताव जो सरकार को भेजे गए, वेबसाइट पर डाल दिए हैं। इसमें उम्मदवारों के नामों पर की गई चर्चा, संबंधित हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए जजों से उनके बारे में ली गई राय और उम्मीदवारों के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के मूल्यांकन को भी सार्वजनिक किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोलेजियम कोई सिफारिश करेगा और उसे सरकार को भेजेगा तो उस प्रस्ताव के विस्तृत कारणों को वेबसाइट पर डाला जाएगा। कोलेजियम के पांच जजों में सीजेआई, जस्टिस जे चेल्मेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, और कुरियन जोसेफ शामिल हैं।

कोलेजियम 1993 में अस्तित्व में आया था जब संविधान पीठ ने एक फैसले में इसका गठन किया था। इसके गठन के साथ ही न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का दखल खत्म हो गया था।

जस्टिस चेल्मेश्वर के प्रयास रंग लाए

कोलेजियम के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस चेल्मेश्वर कोलेजियम की बैठकों में यह कहकर जाने से मना कर दिया था कि जब तक कोलेजियम के विचार विमर्ष को पर्दे के पीछे रखा जाएगा वह बैठकों में नहीं जाएंगे। जस्टिस चेल्मेश्वर जजों की नियुक्ति के लिए लाए गए मोदी सरकार के नए कानून एनजेएसी को निरस्त करने वाले वाली पांच जजों की पीठ के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कानून को सही बताया था। उन्होंने न सिर्फ एनजेएसी को सही ठहराया था बल्कि जजों की नियुक्ति कीमौजूदा प्रणाली कोलेजियम को अपारदर्शी निष्प्रभावी भी बताया था।

आरटीआई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी

सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम के फैसलों को आरटीआई कानून के तहत देने से कई बार मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह जानकारी विश्वास के रूप में सीजेआई कार्यालय में रखी होती है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है।

एमओपी पर उम्मीद जगी

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से सरकार काफी उत्साहित है। सरकार को उम्मीद लगी है कि एमओपी (जजों की नियुक्ति का ज्ञापन) जिस पर सुप्रीम कोर्ट के साथ खींचतान चल रही है, पर कोई समाधान निकलेगा। सरकार की मुख्य मांग है कि उसे देश की सुरक्षा के नाम पर कोलेजियम की किसी भी सिफारिश को खारिज करने का अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्ति सचिवालय हो। नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले से उसे एक स्क्रीनिंग कमेटी को दिखाया जाए।

डाकघर जमा, पीपीएफ, केवीपी के लिए अब आधार जरूरी

नई दिल्ली। सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा जमाकताओं को 12 अंक की अपनी विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। 29 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कायार्लय

में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं। सरकार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है। इसके पीछे का मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है। पिछले महीने सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी। इस विस्तार के दायरे में 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इनमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा योजनाएं आएंगी।

तरीके में हो बदलाव

फांसी देते समय किसी व्यक्ति का बना रहे सम्मान

नई दिल्ली। सजा देने के तरीके में बदलाव करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। ये याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले शख्स को शांति से मरना चाहिए ना कि दर्द से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मारते समय व्यक्ति का सम्मान बना रहना चाहिए। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले दोषी व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाता है जिससे उसका सम्मान नहीं रहता है। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब तीन हफ्ते बाद करेगा। सीजेआई की कोर्ट ने कहा कि अमोरिका

में जहरीला इंजेक्शन देने की काफी आलोचना होती है। सरकार को आधुनिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील तरीके को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान संवेदना का सम्मान करता है। सीआरपीसी की धारा 354(5) में गले से लटकाकर फांसी देने का प्रावधान है जिसे संविधान पीठ ने सही ठहराया है। याचिकाकर्ता ने कहा वह इस प्रावधान को चुनौती नहीं दे रहा है उसे फांसी देने के तरीके पर आपत्ति है।

सहयोग से देश की शक्ति हो जाती है दोगुनी : योगी आदित्यनाथ

आगरा। भारत की मूल पहचान भारत का आध्यात्म है। देश के सबसे बड़े संगठन के रूप में जब आरएसएस का सहयोग मिलता है तो भारत की शक्ति दोगुनी हो जाती है। हमारे खिलाफ प्रचार तंत्र लगा है, लेकिन जब तक धर्माचार्यो का सहयोग है, संघ के स्वयंसेवकों का सहयोग है भारत का कोई बाल भी बांका नही कर सकता। यह कहना था प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वे वृंदावन में संत विजय कौशल महाराज के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केवल भारत मता की जय बोलने से जय नहीं होगा। उसके लिए आचरण करना होगा। उन्होंने कहा कि अब भारत पहले से भी अधिक सशक्त होकर उभरेगा। शुक्रवार को वृंदावन में संत विजय कौशल महाराज के आश्रम निकुंज वन में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु रामदेव शरीक होने को पहुंचे थे। यहां सबसे पहले रामदेव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो नीतियां बना रहे हैं, उसके साथ सवा सौ करोड़ लोगों का साथ हो तो मोदी के सपनों का भारत बनेगा। राम, कृष्ण, ऋषियों का देश बनेगा। सवा सौ करोड़ लोग पुरुषार्थ करेंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी। जब तक मैं अपने राष्ट्र धर्म, स्वधर्म में जुटा हूं तब तक कोई दुनियां में हमें गिरा नही सकता और मैं गिर गया तो कोई उठा नही सकता। राम का देश बनाना है तो राम जैसा आचरण करना चाहिए। रामदेव बोले योगी ने छुट्टियों की छुट्टी करके साहस का काम क्या है। रोज छुट्टी होगी तो पुरुषार्थ कब करेंगे। अमेरिका में लाख दुर्गुण हों, लेकिन वहां के नागरिक पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए उनके पास सब कुछ है। पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को वह डब्लूएचओ के माध्यम से नियंत्रित करता है। वह दुनिया की करेंसी की कीमत तय करता है। अमेरिका से आगे जाना है तो एक हजार लाख करोड़ जीडीपी करनी होगी। इसमें एक हजार करोड़ पतंजलि देगा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि डब्लूएचओ का मुख्यालय भारत में हो। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जो कुछ कहते, सोचते, बोलते हैं, वो कभी समाप्त नही होता, बल्कि अपनी ध्वनि तरंगों के माध्यम से पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। निकुंज वन के सुरम्य वातावरण ने हमें आह्लादित किया। संत विजय कौशल की कथाएं सुनते थे, कभी आने का अवसर नही मिला। आज सौभाग्य मिला है। भारत की मूल पहचान भारत का अध्यात्म है। तमाम झंझावात झेलकर भी भारत, भारत बना है तो उसके कारण हैं। मंदिर, धर्माचार्य और धर्म आचरण। जब तक ये चीजें रहेंगी भारत की राह में कोई बाधा नही आ सकती।

2019 में प्रधानमंत्री बनने की बात पर मुस्कुराए राहुल

रायबरेली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को भूएमऊ गेस्ट हाउस में रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि सच्चे सिपाही की तरह वह उनके संघर्ष में हर समय साथ रहेंगे। एक कार्यकर्ता ने उन्हें गुलाब का फूल देते हुए कहा कि आप 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर राहुल सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गरीबों के हित के मुद्दे जनता के बीच में उठाते रहने को कहा। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के तीन दिन के दौरे पर आए कांग्रेस उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आखरी दिन भूएमऊ गेस्ट हाउस में शुक्रवार की रात पहुंचे थे। रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने रात में उनको बुके देकर अगवानी की। सुबह उनसे मुलाकात के लिए रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस पहुंचे। करीब 11 बजे राहुल सबसे बारी-बारी से मिले। इस बार कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका अंदाज भी बदला हुआ था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग फोटो सेशन भी खुद से कराया। राहुल के इस बदले अंदाज से कार्यकर्ता काफी खुश दिखे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीके शुक्ला ने उन्हें गुजरात में किए जा रहे संघर्ष की बधाई दी और कहा कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को तैयार है। जिला महासचिव प्रमेंद्र पाल सिंह गुलाटी ने बुके देते हुए जैसे ही यह कहा कि आप 2019 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वैसे ही राहुल के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। हालांकि उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज किया। कार्यकर्ता राजकुमार दीक्षित, अजीत सिंह, नौशाद खतीब, सुनील तिवारी, राकेश सिंह राणा, प्रमोद त्रिपाठी, रोहित बाजपेई और लाल आश किरण प्रताप सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे जमीनी संघर्ष के लिए बधाई दी और आश्वस्त किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ संघर्ष में रायबरेली के कार्यकर्ता पीटे नहीं रहेंगे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष से सईदउल हसन ने अब तक किए गए आंदोलनों और संघर्षों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अवगत

कराया। पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे दिल्ली के लिए अमौसी जाते वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष का शहर के साथ-साथ हरचंदपुर बछरावां कुंदनगंज में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया।

अपनी बुद्धि से साधु होना अच्छा, पराई बुद्धि से राजा होना अच्छा नहीं -लोकोक्ति

विकास दर अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति समीक्षा में विकास दर अनुमान को वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, जो 6.7 प्रतिशत किया है, उससे किसी को आर्श्चय नहीं होना चाहिए। जब विकास दर थोड़ी ठीक रहने की संभावना थी तो उसने पिछले अनुमान में इसके 7.3 प्रतिशत रहने का आकलन किया था। पहली तिमाही की विकास दर 5.7 प्रतिशत आ गई और उसके पास संबंधित आर्थिक गतिविधियों के तय भी उत्साहजनक नहीं थे। इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगे इसमें वृद्धि ही होनी है। मसलन, दूसरी तिमाही में विकास दर 6.4 प्रतिशत, तीसरी में 7.1 प्रतिशत एवं चौथी तिमाही में यह 7.7 प्रतिशत हो जाएगी। यानी आने वाले समय में हमें विकास दर चढ़ती हुई मिलेगी। आरबीआई ने पहली तिमाही में विकास दर कमजोर होने के साथ खरीफ फसल पैदावार का पहला अग्रिम अनुमान कम आना और जीएसटी क्रियान्वयन में समस्याएं बने रहने को प्रमुख कारण माना है। आखिरी दौर में मॉनसून के ठीक न रहने से खरीफपैदावार घटने की आशंका है। इसका असर सकल विकास दर पर पड़ना ही है। उसकी यह बात भी सही जान पड़ती है कि अगर जीएसटी के क्रियान्वयन का प्रतिकूल प्रभाव अब तक बना हुआ जान पड़ता है तो कम-से-कम अल्पकाल में विनिर्माण क्षेत्र के लिए संभावना अनिश्चित बनी रहेगी। मतलब इससे औद्योगिक गतिविधियों में अवरोध कायम रहेगा। जाहिर है, इससे निवेश गतिविधियों में और देरी हो सकती है, जो बैंकों और कंपनियों के बही-खातों पर दबाव के कारण पहले से प्रभावित है। इसमें विकास दर की तीव्र वृद्धि निश्चय ही मुश्किल है। हां, इसका यह भी अर्थ हुआ कि अगर जीएसटी क्रियान्वयन को संभाल लिया गया तो इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। किंतु जब तक ऐसा होगा समय काफी बीत चुका होगा, इसलिए विकास दर को एक सीमित सीमा तक ही रखा जा सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि दूसरी तिमाही में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का उसके द्वारा जो सर्वे किया गया, उसमें ग्राहकों का भरोसा और कुल मिलाकर व्यापार आकलन कमजोर होने का निष्कर्ष आया। किंतु मौद्रिक नीति समिति द्वारा की गई समीक्षा का एक सकारात्मक पहलू यह है कि कंपनियां तीसरी तिमाही में व्यापार माहौल सुधरने की उम्मीद कर रही हैं। यही उम्मीद है जो भविष्य के लिए विकास दर के नीचे गिरने की संभावना नहीं दर्शाते।

राजनीतिक हिंसा की बेल

वामपंथ के गढ़ केरल में भाजपा-संघ ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। सूबे में पिछले कई वर्षो से हो रही राजनीतिक हत्याओं ने हालिया वक्त में देश-दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है। एक तरफ जहां भाजपा व संघ सियासी हत्याओं को वामपंथी दलों द्वारा किया गया कृत्य मानती है तो वहीं वामपंथी दल इसके लिए भाजपा-संघ को दोषी ठहराते हैं। राजनीतिक हिंसा की बेल बेहद खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। आंकड़े भी इसकी तसदीक करते हैं। 2001 से अब तक प्रदेश में 120 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं जबकि केरल पुलिस के आंकड़े के अनुसार 2001 से अगस्त 2017 तक कुल 85 वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं जबकि 65 संघ-भाजपा कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या संघ-भाजपा वाकई केरल में सियासी हत्याओं के खिलाफ हैं या उनका मकसद यहां कैसे भी शासन में आना है? वैसे, जिस रणनीतिक चपलता के साथ भाजपा यहां माहौल बनाने में जुटी है, उससे इतना साफ पता चल जाता है कि वह दक्षिण भारत के कर्नाटक जैसी मजबूत उपस्थिति यहां भी दिखाना चाहती है। तमिलनाडु में एआईडीएमके और भाजपा मिलकर चुनावी समर में आएंगी ही। केरल इसलिए अहम है कि भाजपा यहां से दक्षिण के बाकी राज्यों को भी यह संदेश देना चाहती है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भी उसके लिए अहम है। इसलिए वह राजनीतिक हत्याओं के साथ-साथ लव जेहाद का मसला भी उसी अनुपात में उठा रही है। दक्षिणपंथी पार्टी को इस बात की टीस जरूर होगी कि जब वामपंथ के सारे गढ़ एक-एक कर ढह रहे हैं तो उसकी मौजूदगी केरल में ही क्यों रहे? लेकिन भाजपा-संघ को भी इस बात को समझना होगा कि सिर्फ धर्म और राजनीतिक हिंसा के मसले को हवा देकर जनता के दिलो-दिमाग में जगह नहीं बनाई जा सकती? इसके लिए विकास के वे सोपान भी विकसित करने होंगे, जिसकी बदौलत केरल आज देश का सबसे साक्षर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना, अन्य राज्यों की तुलना में आबादी का कम वृद्धि दर व उच्च शिक्षा की सुविधा वाला राज्य है। वामशासित त्रिपुरा भी सुशासन का बेहतर उदाहरण है। वैसे भी अभी तक भाजपा ने केरल सरकार के कामकाज और उसकी कार्यशैली को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है। हालांकि इन सब मुद्दों को उठाए बिना अगर भाजपा अपना वोट फीसद 6.4 से 10.3 करने में कामयाब रही है तो इसे भी संजीदगी से समझने की जरूरत है।

''खबरों में बने रहने की कवायद'

भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर के कम रहने जाने की भविष्यवाणी कर चुका है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, वृद्धि दर 7.3 के कम होकर 6.7त्न रह जाएगी। खरीफ के खाद्यान्न उत्पादन में कमी के अनुमान, जीएसटी से विनिर्माण क्षेत्रपर प्रतिकूल प्रभाव, निवेश गतिविधियों में सुधार न होने और उपभोक्ता और कारोबारी धारणा नरम रहने से 2017-18 की प्रथम तिमाही में समग्र वृद्धि के धीमा पड़ जाने के चलते केंद्रीय बैंक ने यह अनुमान जताया है। जिस दिन केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था की यह धुंधली तस्वीर पेश की थी, उसी दिन को प्रधानमंत्री ने अपने ``तय' पेश करने को चुना। यह कुछ नहीं बल्कि ``खबरों में बने रहने की कवायद' है।

सतीश पेडणोकर

प्रधानमंत्री नीतिगत दुविधा के शिकार हैं। जरूरी है कि प्रति-चक्रीय वित्तीय नीति अपनाईजाए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज शुल्क में पिछले दिनों 2 रुपये की कटौती इसी सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि यह आधे मन और अधूरे तरीके से उठाया गया है। बहरहाल, मोदी विमुद्रीकरण, जीएसटी, डिजिटलाइजेशन और नकदीरहित अर्थव्यवस्था के शोर-शराबे में ही भ्रमित बने हुए हैं। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में बताने वाले आलोचकों पर हाल में जिस तरह फट पड़े उससे उनकी बेचैनी, जो शेखी पीछे छिपी थी, उसका पता चलता है। ऐसा होता है जब नीति-निर्माण बाजीमार-भाव का बंधक बन जाता है, ठोस आर्थिक आंकड़ों और बुनियादी कारकों के बजाय कोरी भावनाओं और अवधारणाओं पर टिक रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर के कम रहने जाने की भविष्यवाणी कर चुका है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, वृद्धि दर 7.3त्न के कम होकर 6.7त्न रह जाएगी। खरीफ के खाद्यान्न उत्पादन में कमी के अनुमान, जीएसटी से विनिर्माण क्षेत्रपर प्रतिकूल प्रभाव, निवेश गतिविधियों में सुधार न होने और उपभोक्ता और कारोबारी धारणा नरम रहने से 2017-18 की प्रथम तिमाही में समग्र वृद्धि के धीमा पड़ जाने के चलते केंद्रीय बैंक ने यह अनुमान जताया है। जिस दिन केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था की यह धुंधली तस्वीर पेश की थी, उसी दिन को प्रधानमंत्री ने अपने ''तय' पेश करने को चुना। यह कुछनहीं बल्कि ''खबरों में बने रहने की कवायद' है। मोदी ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान आठ मौकों पर जीडीपी की वृद्धि दर मौजूदा स्तर 5.7त्न (प्रथम तिमाही : 2017-18) से नीचे गई। यह तुलना बेतुकी है क्योंकि जनवरी, 2015 के बाद से ही जीडीपी के आकलन का तरीका बदल चुका है। इसलिए एनडीए और यूपीए के शासनकाल की तुलना ही इस लिहाज से बेमानी है। पुराने अनुमानों के मुताबिक, दरअसल, प्रथम तिमाही : 2012-13 और चौथी तिमाही : 2013-14 के मध्य की आठ तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि दर 4.3त्न से 5.2त्न के बीच रही। लेकिन नये अनुमानों के अनुसार उन आठ तिमाहियों की चार तिमाहियों में जीवीए में वृद्धि 5.7त्न से कहीं ज्यादा थी। 2011-12 की दूसरी तिमाही में यह 7त्न थी और 2013-14 की प्रथम और तीसरी तिमाही के दौरान 6.3त्न और 7.1त्न के बीच रही। तो क्या प्रधानमंत्री जीडीपी आकलनों की पुरानी श्रृंखला का उल्लेखकर रहे थे या जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडिशन) आकलनों की नईश्रृंखला का? यदि पुरानी श्रृंखला का जिक्र कर रहे थे तो जीडीपी की वृद्धि दर मौजूदा तिमाही में ही 5.7त्न से भी कम ठहरेगी। अगर वह नई श्रंखला के जीवीए वृद्धि संबंधी आकलनों का उल्लेख कर रहे थे तो कुछसाबित नहीं कर पाए। आकलन के भिन्न तरीकों के आधार पर दो आंकड़ों की गलत सांख्यिकीय तुलना करने के बजाय मोदी को नईआंकड़ा श्रृंखला के जीवीए वृद्धि संबंधी आंकड़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जिन्हें उनके शासनकाल में तैयार किया गया है। दो तय उल्लेखनीय हैं : पहला, आज जीवीए की वृद्धि दर (प्रथम तिमाही : 2017-18 में 5.5%) उस दर (दूसरी तिमाही : 2014-15 में 8.5%) से काफी नीची है, जब मोदी से पद संभाला था। दूसरा, बीती पांच तिमाहियों में जीवीए की वृद्धि दर गिरी है। प्रथम तिमाही : 2016-17 में यह 7.5त्न थी, गिरकर प्रथम तिमाही : 2017-18 में5.6त्न रह गई। क्या यह आर्थिक शिथिलता नहीं है, तो क्या है? ऑटोमोबाइल्स की बिक्री और हवाईजहाज से यात्रा करने वालों के जो आंकड़े प्रधानमंत्री ने पेश किए हैं, वे समाज के खाते-पीते तबके की उपभोक्ता मांग से संबंधित हैं। लेकिन सतत आर्थिक वृद्धि निवेश चालित होती है। भारत में निवेश की दर, जो 2008 की नियंतण्र मंदी से पूर्व 40% के स्तर को छू गईथी, 2016-17 में गिरकर 30त्न के स्तर पर आ गई। एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक में यह दर 37त्न से ज्यादा है। तो फिर, ''सबसे तेज गति से विकास करती अर्थव्यवस्था'का दावा क्यों? वह भी उस सूरत में जब भारत के समतुल्य आर्थिक हैसियत वाले देशों में निवेश दर भारत की तुलना में ऊंची है। सच तो यह है कि वास्तविक निवेश वृद्धि धड़ाम से गिरी है। प्रथम तिमाही :2016-17 में यह 7.4% थी, तो चौथी तिमाही :2016-17 में -2.1% रह गई। प्रथम तिमाही:2017-18 में यह 1.6त्न थी। औद्योगिक ऋण में महीनावार वृद्धि अक्टूबर, 2016 से ही नकारात्मक बनी हुई है। विनिर्माण आईआईपी की वृद्धि में गिरावट रही। सीएसओ और आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के समय में देश में निजी निवेश को खासा झटका लगा है। सीएमआईई कैपेक्स के आंकड़ों के मुताबिक, रुकी पड़ी परियोजनाओं की लागत बीती पांच तिमाहियों में वृद्धि हुईहै। प्रधानमंत्री 400 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में डंका पीटने के अंदाज में बताया है। तो फिर इस बात का भी जिक्र कर दिया होता कि आज भारत का बाह्य ऋण 485 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। आरबीआईपहले ही निर्यात की तुलना में आयात के तेजी से बढ़ने पर अपनी चिंता से अवगत करा चुका है। साथ ही, हाल के समय में विदेशी पूंजी आगम में ऋण के बढ़ते अनुपात के बारे में भी कह चुका है।

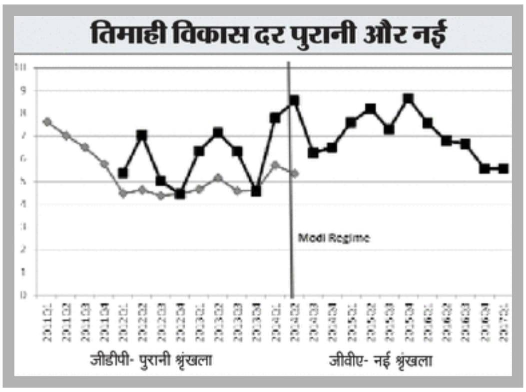

चालू खाते की चौड़ी होती खाई को विदेशी ऋण से पाटने का ही नतीजा था कि यूपीए के शासनकाल में जुलाई-अगस्त, 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन के संकट में फंस गईथी। जाहिर है कि इस मोर्चे पर कोताही से भारत का संकट बढ़ सकता है। दरअसल, प्रधानमंत्री नीतिगत दुविधा के शिकार हैं। जरूरी है कि प्रति-चक्रीय वित्तीय नीति अपनाईजाए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज शुल्क में पिछले दिनों 2 रुपये की कटौती इसी सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि यह आधे मन और अधूरे तरीके से उठाया गया है। बहरहाल, मोदी विमुद्रीकरण, जीएसटी, डिजिटलाइजेशन और नकदीरहित अर्थव्यवस्था के शोर-शराबे में ही भ्रमित बने हुए हैं, और उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ के साथ ही डूब भी सकता है।

चलते चलते

''जमीन समाधि सत्याग्रह'

अधिग्रहण पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में बेहद संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। चूंकि भूमि से व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव तो रहता ही है, साथ में उसकी पहचान भी जुड़ी होती है। लेकिन देश में जब भी जमीन अधिग्रहण की पहल सरकार या निजी कंपनियों द्वारा ली जाती है, विरोध के स्वर ज्यादा तेजी से बुलंद हो जाते हैं। विरोध की इसी कड़ी में नाम आया है राजस्थान का। यहां विरोध का तरीका चौंकाने वाला है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं? हर कोई गर्दन तक गहरे गड्ढों में बैठकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इनकी तस्वीरें देशभर के समाचार माध्यमों में छायी हुई हैं। मामला जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक आवासीय परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का है। जहां प्राधिकरण द्वारा ली गई 1350 हेक्टेयर भूमि के विरोध

> देश में जब भी जमीन अधिग्रहण की पहल सरकार या निजी कंपनियों द्वारा ली जाती है, विरोध के स्वर ज्यादा तेजी से बुलंद हो जाते हैं। विरोध की इसी कड़ी में नाम आया है राजस्थान का। यहां विरोध का तरीका चौंकाने वाला है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं? हर कोई गर्दन तक गहरे गड्ढों में बैठकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इनकी तस्वीरें देशभर के समाचार माध्यमों में छायी हुई हैं।

में किसानों ने ''जमीन समाधि सत्याग्रह' शुरू कर दिया। सरकार द्वारा सार्वजनिक कायरे के लिए भूमि का अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हाल के दशकों में विरोध के स्वर इतने मुखर क्यों हुए हैं? इसकी तह में जाएं तो पहला कारण; उचित पुनर्वास और दूसरा बाजार की कीमत पर जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलना है। पूर्व के अधिग्रहण ऐसे उदाहरणों भरे पड़े हैं। सरदार सरोवर बांध इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां कई दशकों बाद भी विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हो पाया। दरअसल, कई अधिग्रहण मामले में सरकार बिचौलियों की भूमिका में दिखती है। यानी औने-पौने दामों पर लोगों से जमीनें लेकर उद्योगपतियों को सौंप देती है।

बड़े पैमाने पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीनें दशकों बाद यों ही खाली पड़ी हैं। ये सभी बातें लोगों को सरकार के प्रति अविास और आक्रोश को जन्म देती हैं। लेकिन इस अविास और आक्रोश की शिकार कई बेहद जरूरी और राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाएं हो जाती हैं। सच्चाई यह भी है कि बिना भूमि के कई परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं। अत: किसी भी प्रकार के भू-अधिग्रहण से पहले लोगों को विास में लेना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुद्दा

नदियों के मीठे पानी

बुधवार 4 अक्टूबर को एक बार फिर वही हुआ जो अक्सर होता रहा है। महंगाई को थामने कीचिंता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विद्वतजनों पर तारी रही और उन्होंने नीतिगत प्रमुख दरों में कटौती करने से परहेज किया। उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं कि चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर में पहले से ही गिरावट के अनुमान व्यक्त किए जा चुके हैं और देश में मैन्युफैक्चिरिंग से लेकर पूरे अनौपचारिक क्षेत्र तक खासकर, जीएसटी को लेकर बदहाली की स्थिति है। मांग में कमी, निर्यात क्षेत्र की कमजोरी, इन सबका देश में रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसकी सरकार फिक्र करती तो नजर आती है पर जब ऐसे अवसर आते हैं तो चूक जाती है। देखा जाए तो सरकार के लिए प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करने का अभी माकूल समय था क्योंकि महंगाई चाहे लाख सिर उठा रही हो, लेकिन बहुत हद तक वह नियंतण्रके दायरे में ही है। पर इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा से ही दुविधा में दिखता नजर आया है। विकास दर के मुकाबले, महंगाई उसकी प्राथमिकता में हमेशा आगे रही है। दरअसल, सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मोर्चो पर परेशानियों का सामना कर रही है। सरकार चाहे लाख दुहाई दे। लेकिन सच्चाई यही है कि वह जीएसटी से देश के खासकर, छोटे और मझोले उद्योग धंधों पर पड़ने वाले असर से बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर न केवल सरकार की चिंताओं की बात की बल्कि यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल इस पर पूरा विचार रही है और इसके बहुत आसार हैं कि जीएसटी की वर्तमान उच्च दरों में कमी की जाएगी और उद्यमियों की दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ, महंगाई डायन भले ही अभी बेकाबू न हुई हो मगर इसके लक्षण फिलहाल अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मुद्रास्फीति दर पांच माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में खासा इजाफा हो चुका है। कोर महंगाई दर, जिसमें खाद्य वस्तुएं और इंधन शामिल नहीं हैं, में भी तेजी आई है।

''कोढ़ में खाज' यह है कि आने वाले समय में हालात और खराब हाने के ही आसार हैं क्योंकि खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान भी बहुत अनुकूल नहीं है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने जीडीपी अनुमान को इस वर्ष घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया, जबकि अगस्त में 7.3 प्रतिशत की भविष्यवाणी की गई थी। जीडीपी पहली तिमाही में गिर कर 5.7 प्रतिशत पर आ चुकी है और पिछली पांच तिमाहियों से इसमें लगातार गिरावट आ ही रही है। जीडीपी वृद्धि दर की गिरावट ने दर्शा दिया है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के महत्त्वाकांक्षी कदमों ने कम-से-कम अल्प अवधि में अर्थव्यवस्था को जरूर नुकसान पहुंचाया है। सरकार पर विकास दर को बढ़ावा देने के लिए अब प्रोत्साहन पैकज देने का दबाव भी बढ़ने लगा है। यह तय है कि अगर सरकार के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं है। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए सरकारें चाहे वे किसी भी दल की क्यों न हों, ऋण माफी जैसे कदमों को बढ़ावा देती रही हैं और मौजूदा सरकार भी इसका कोई अपवाद नहीं है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए।

सरकार को खासकर, बुनियादी ढांचों से संबंधित अंतराल को पाटने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र से जुड़ी अहम निवेश परियोजनाओं को जितना जल्द अमलीजामा पहना दिया जाए, देश के विकास के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। व्यवसाय करने की सुगमता को लेकर बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती रही हैं किंतु वे दिखें भी, यह सुनिश्चित करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने बेशक यह कहा हो कि देश में सुधार से संबंधित दर्जनों फैसले लिये जा चुके हैं, लेकिन वे सुधार जमीनी स्तर पर भी दिखाई दें, इसकी दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

बंदूक संस्कृति तो लहूलुहान ही करेगी

आभा स्वामी

जब हमारा देश अहिंसा के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, तकरीबन उसी वक्त अमेरिका हिंसा के खूनी तांडव से लहूलुहान हो गया। दुनियाभर में जुएघर की राजधानी के रूप में ख्यात अमेरिका के आलीशान शहर लास वेगास में एक 64 वर्षीय बंदूकधारी शख्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 500 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। अमेरिका में इस साल सरेआम गोलीबारी (मास शूटिंग) की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गौरतलब यह है कि ये कोई आतंकी वारदातें नहीं थीं और इनमें से कुछ घटनाओं की ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। अमेरिका में इस साल सिर्फ जून के महीने में ही गोलीबारी की 19 वारदातें हुई थीं, जिनमें 44 लोग मारे गए। अमेरिकी कांग्रेस के एक मौजूदा सदस्य ऐसी ही एक वारदात में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगस्त, 2017 में गोलीबारी की ऐसी वारदातों में मौत का आंकड़ा 26 रहा, वहीं सितंबर में 23 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश अखबार 'गार्जियन का आकलन है कि अमेरिका में वर्ष 2013 से लेकर अब तक सरेआम गोलीबारी की वारदातों में 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6500 से अधिक घायल हुए हैं। लास वेगास में रविवार रात हुए हिंसक तांडव से कुछ घंटे पहले ही मध्य अमेरिका के कंसास में एक व्यक्ति ने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खूनी वारदातों के इस सिलसिले को देखते हुए अमेरिका की 'बंदूक संस्कृति पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या अमेरिकियों को गोलीबारी में मजा आता है, क्योंकि उनके लिए बंदूक हासिल करना सहज है? लास वेगास में तो 21 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी शख्स बगैर किसी परमिट के बंदूक खरीद व इसे लेकर खुलेआम घूम सकता है। अमेरिका में ऐसे अधिकतर बंदूकधारी हत्यारे दिमागी रूप से परेशान शख्स पाए गए, जो अपनी जिंदगी से नाखुश होने की वजह से दुनिया से भी खफा होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ष 1917 में ग्वालियर के महाराजा का स्तर बढ़ाते हुए '21 बंदूकों की सलामी का कर दिया गया, लेकिन इंदौर और भोपाल के शासक 19 बंदूकों की सलामी के ही हकदार थे। आज के शासक (या कहें कि राजनेता) भी हथियार रखना पसंद करते हैं। हमारे यहां शादी-ब्याह जैसे समारोह केजश्न में बंदूक से फायर करने की घटनाएं आम हैं। इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। पिछले साल ही एक दूल्हे की बारातियों द्वारा चलाई गोली से मौत की हृदयविदारक घटना सामने आई थी। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में अवैध हथियारों का धंधा फल-फूल रहा है। आज के इस मुश्किल दौर में जहां आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपलब्धता काफी कम है, आत्मरक्षा के कुछ साधन होना (खासकर महिलाओं के लिए) तो बेहद जरूरी हैं। 'स्टन गन, 'टेजर गन या 'मिर्च स्प्रे गन जैसे कुछ ऐसे साधन उपलब्ध भी हैं, जो ज्यादा घातक नहीं। लेकिन अफसोस कि सरकार ने इन साधनों का इस्तेमाल वैध नहीं बनाया है। स्टन गन का इस्तेमाल लंबी दूरी से ही आपके विरोधी को नि:शक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री की 'नमामि देवी नर्मदे यात्रा से नदी के आसपास जागरूकता आई है। पर बड़े स्तर पर नर्मदा में काम करने के लिए जो नर्मदा मिशन बनाया गया है, सरकार ने जो कार्ययोजना बनाई है, उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। सरकार के स्तर पर 2 जुलाई को 6 करोड़ पौधे रोपने का जो लक्ष्य रखा था, उसके परिणाम जरूर नर्मदा की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते कि पौधे ज्यादा संख्या में जीवित रहें।

सत्संग

नम्रता, दान, उपहार

अस्तित्व दो चीजों से मिलकर बना है ''वह जो है' और ''वह जो नहीं है'। ''वह जो है' में आकार-प्रकार, रूप, गुण, सुंदरता है जबकि ''वह जो नहीं है' में ये चीजें नहीं होती। मगर वह मुक्त होता है। ''वह जो नहीं है' कहीं-कहीं ''वह जो है' में फूट पड़ता है। जैसे-जैसे ''वह जो है' अधिक चेतन होता जाता है, वह ''वह जो नहीं है' बनने के लिए लालायित हो जाता है। हालांकि हमें उसके रूप-गुण, विशेषताएं और सुंदरता अच्छी लगती है, मगर अस्तित्व की पूर्ण आजादी की अवस्था को पाने की लालसा से हम बच नहीं सकते। यह सिर्फ समय की बात है और समय और स्थान का बंधन भी ''वह जो है' का एक छलावा है। ''वह जो नहीं है' को समय या स्थान का बोध नहीं होता क्योंकि वह असीम और शाश्वत है। वह समय और स्थान की सीमाओं की बेड़ियों से मुक्त है। जब अस्तित्व की मूल प्रक्रिया से आजाद होने की यह लालसा पैदा होती है, तो मन और भावना की आशंकापूर्ण प्रकृति इसे आत्म-विनाश के रूप में देखने लगती है। एक विचारशील मन के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया जानते-बूझते हुए आत्महत्या करने जैसा है। मगर यह आत्महत्या नहीं है, उससे कहीं आगे की चीज है। आत्महत्या अपना अंत करने की चाह का एक खराब तरीका है। खराब से मेरा मतलब है कि यह तरीका असफल होता है। यह कारगर नहीं होता। मगर इस संस्कृति में कुछ लोग इसे कारगर तरीके से करने में निपुण होते हैं, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भारत में ''समाधि' शब्द आम तौर पर कब्र या स्मारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है और उसके ऊपर किसी तरह का स्मारक बनाया जाता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। जिसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जब किसी व्यक्ति के मरने पर उसे दफनाया जाता है, तो उस स्थान को उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी खास जगह पर एक खास अवस्था को हासिल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उस स्थान का नाम दे दिया जाता है। इसी वजह से कई योगियों का नाम किसी खास जगह के नाम से मिलता है। श्री पलानी स्वामी को यह नाम ऐसे ही मिला क्योंकि वह पलानी नामक जगह पर समाधि में बैठे। लोगों ने उन्हें पलानी स्वामी कहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने कभी लोगों को अपना नाम नहीं बताया।

कानपुर में 3 दनि में दूसरा वस्फिोट से हड़कंप, भारी मात्रा में बम-बारुद बरामद-एक आरोपी अरेस्ट

कानपुर.यहां के सरसौल इलाके में शुक्रवार को एक बार फरि बम वस्फिोट होने से हड़कंप मच गया। सूचना मलिते ही पुलसि मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कयिा। इस दौरान कई बोरों में भरा बारुद, करीब 6 कलिो देसी बम और अवैध पटाखे बरामद कएि गए। हालांक, कसिी के हताहत होने की खबर नहीं है। जांच अधकिारयिों की मानें तो अगर बरामद बारुद और बम वस्फिोट हो जाता तो पूरे बल्डिगि को तहस-नहस कर देता। बता दें, दो दनि पहले सरसौल में ही बम बलास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलसि ने इस मामले में धमाके के मुख्य आरोपी बाबू सहि को हाथी गांव से गरिफ्तार कयिा है। सरसौल गांव की महिला ग्राम प्रधान किरण शुक्ला के पति रज्जन शुक्ला ने बताया, गांव में भले ही लोगों को पटाखे बनाने का लाइसेंस प्रशासन नहीं दे रही हो, लेकनि लोग अवैध तरीके से यहां पटाखा बनाने का काम करते हैं।

यहां अवैध पटाखे बनाने के बारे में पुलिस चौकी और महाराजपुर थाने को भी जानकारी है, लेकनि पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं करती।

आरोप है कि अगर किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी तो पुलिस उल्टा सूचना देने वाले पर ही कार्रवाई कर देती है। ऐसे में गांव का कोई भी व्यक्ति पुलिस को कोई जानकारी नहीं देता है। अवैध पटाखा बनाने का का काम पुलिस के ही संरक्षण में ही चल रहा है।

बंद कमरे में होता बलास्ट हो सकता था बड़ा हादसा

रमेश कोरी के खाली पड़े प्लॉट में हुए धमाके को लेकर पड़ोसी राम सजीव शुक्ला ने बताया, अगर ये धमाका बंद मकान में होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। धमाका बहुत तेज था। प्लॉट में पानी डालकर वस्फिोटक को नष्क्रियि कयिा गया।

एसपीआरए जीपी सिंह ने बताया, जिस प्लॉट में विस्फोट हुआ उसमें पटाखे और बारुद छुपाए गए थे। घटनास्थल से करीब 250 सुतली बम बरामद हुए हैं। कई संदिग्ध के घर भी तलाशी ली जाएगी। बरामद वस्फिोटक दीपावली में इस्तेमाल किए जाने वाले देसी पटाखों के बारुद हैं।जांच अधिकारी आरपी सिंह के मुताबिक, एक प्लॉट से 1 बोरी में करीब 300 देसी बम बरामद हुए हैं। इतना बारुद एक बिल्डिंग को गरिाने में सक्षम है। फलिहाल बरामद हुए सारे देसी बम को निष्क्रिय कर दफनाया जा रहा है जिसे महराजपुर थाने में किया जा रहा है।

दो दनि पहले वस्फिोट में 4-5 घरों के उड़ गए छत

महराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सरसौल कस्बे के एक मकान में देशी पटाखे बनाए जाने का काम चल रहा था। जहां तेज धमाका हो जाने से मकान में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। वही धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के करीब 4 घर भी इसकी चपेट में आ कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का आगाज, नामांकन हुआ पूरा

इलाहाबाद. ईस्ट के ऑक्सफ़ोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव का आगाज शुक्रवार को हो गया। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने के साथ परिसर में अराजकता का माहौल बनना शुरू हो गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र नेताओ ने नामांकन किया।

अधिकारियों ने क्या कहा...

एसएसपी आन्नंद कुलकर्णी ने कहा, ''छात्र संघ चुनाव का नामांकन पूरा हुआ। इस दौरान लोग अपनी दक्षता दिखाने के लिए सड़कों पर छात्र नेताओं शक्ति प्रदर्शन किया। जिसके चलते प्रशासन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चुनाव अधिकारी आरएन सिंह ने कहा, ''चुनाव का नामांकन पूरा हो गया है।

3 महीने से मदद के इंतजार में भटकती रही मां, रिश्वत के चक्कर में नहीं भेजी फाइल

फतेहपुर(यूपी). यहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक लड़के की मौत हो गई। दरसल, एक महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए यूपी सीएम से गुहार लगाई थी। बेटे के इलाज के लिए उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता भी मिल गई थी। लेकिन जिले के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने 3 महीने से रिश्वत के चलते फाइल पर साइन तक नहीं किया, इस दौरान रविवार को लड़के की मौत हो गई। इसके बाद महिला ने सदर विधायक के साथ सीएमओ ऑफिस पहुंचकर हंगामा करने लगी। इसके बाद डिप्टी सीएमओ ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मामला फतेहपुर के थरियांव थाना क्षेत्र के शाहीपुर गांव का है। यहां की रहने वाली रन्नो देवी के बेटा सिद्धार्थ श्रीवास्तव (16) का फेफड़ा खराब हो गया था। उसका इलाज कानपूर के मुरली लाल हॉस्पिटल में चल रहा था।

शुक्रवार को पीड़ित महिला सदर विधायक विक्रम सिंह के साथ सीएमओ ऑफिस पहुंची और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिओं की शिकायत करते हुए हंगामा करने लगी। इसके बाद विधायक विक्रम सिंह ने जब फाइल मंगवाया तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अलमारी में ताला लगाकर फाइल लेकर फरार हो गया था और मोबाइल भी बंद कर दिया था।

- पीड़ित महिला ने बताया, ''मुख्यमंत्री सहायता कोष से बेटे के इलाज के लिए गुहार लगाई थी। 7 जुलाई को कानपुर के अधिकारियों के पास जा-जाकर मैनें सहायता कोष की फाइल पास कराकर अपने जिलें के विभाग ऑफिस में मंगवा लिया था।''
- ''27 जुलाई को मैं जब यहां आई तो वो लोग मुझे फाइल ही नहीं दिखा रहें थे। फिर मेरे दबाव बनाने पर फाइलों का बंडल निकाला तो उसमें मेरी फाइल पड़ी थी। इसके बाद लोग मुझे डॉक्यूमेंट् लाने को बोला मैं तुरंत तहसील जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर लाई। मैं इन लोगों के सामने हाथ भी जोड़े, गिड़गिड़ाया भी लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे।''
- ''इसके बाद मैं वापस कानपुर अपने बच्चे के पास चली गई। वहां से अधिकारियों को कई बार कॉल किया लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर मैं दोबारा कानपुर से वापस यहां आई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाती रही लेकिन ये लोग मुझे टालते रहें।''
- ''इन लोगों को मैने डीएम से शिकायत करने की धमकी तक दी लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। तब जाकर मैंने विधायक विक्रम सिंह का सहारा लिया। उन्होंने ने भी फोन करके बोला लेकिन फिर भी इन लोगों ने फाइल पास नहीं किया। इस दौरान मेरे बच्चे की 1 अक्टूबर को मौत हो गई। अगर मैं इन्हें 5 हजार भी दे देती तो ये लोग फाइल पास कर देते और मेरा बेटा आज जिंदा होता।''

ट्रक से कुचलकर 6 साल के बच्चे की मौत, लोगों ने 3 डम्फर में लगाई आग

भदोही.कोइरौन-गोलखरा मार्ग पर शुक्रवार को डम्फर की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर तीन डम्फरों को आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर भीड़ पर हलका बल प्रयोग कर काबू किया और फायर बिग्रेड से आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

स्कूल से घर लौट रहा था छात्र

6 साल का शिवम तिवारी सरस्वती ज्ञान मंदिर में पहली क्लास में पढ़ता था। स्कूल से घर वापस जाने के लिए सड़क पर निकला और डम्फर की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की, इसके बाद कोइरौना-गोलखरा मोड़ पर चक्काजाम कर दिया। साथ ही उस मार्ग से गुजरने वाले तीन डम्फरों को आग के हवाले कर दिया।

घटनास्थल पर एडीएम ज्ञानपुर, एडिशनल , सीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही।

ग्रामीणों ने बताया कि इस रूट पर मिट्टी लेने के लिए पिछले एक महीने से कई डम्फर चल रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की, इसके बाद कोइरौना-गोलखरा मोड़ पर चक्काजाम कर दिया। साथ ही उस मार्ग से गुजरने वाले तीन डम्फरों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही उस मार्ग से गुजरने वाले तीन डम्फरों को आग के हवाले कर दिया। स्कूल के समय पर डम्फरों को इस रूट से नहीं गुजरने की बात ठेकेदार से बोली भी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

योगी के मंत्री ने आजम को बताया क्रूर-अत्याचारी

अपने समाज पर किया जुल्म

अम्बेडकरनगर.योगी सरकार में मुस्लिम वक्फ बोर्ड व हज मंत्री मोहसिन रजा ने राम मंदिर के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरब में बनेगा। वहीं, आजम पर निशाना साधते हुए कहा कि रामपुर में जौहर ट्रस्ट के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले पूर्व में मंत्री क्रूर नेता(आजम खान) है। जिले में गुरुवार को सीबी सिंह लॉ कॉलेज में श्रद्धांजलि समारोह में आयोजित किया गया था। यहां मंत्री मोहसिन रजा भी शिरकत करने पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा, 'जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकार और जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। हम उसको वापस लेंगे। हमारे पास पूरी फाइल रखी है। उसमें जबरदस्त अनियमितताएं हैं।''

बनाकर उसमें छात्र पढ़ाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। चाहे मंत्री जी कुछ भी करलें उनको ट्रस्ट छोड़ना होगा।'' रजा भी शिरकत करने पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा, 'जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकार और जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। हम उसको वापस लेंगे। हमारे पास पूरी फाइल रखी है। उसमें जबरदस्त अनियमितताएं हैं।''

के मसीहा बनने वाले पूर्व में मंत्री क्रूर नेता(आजम खान) है।

सबसे ज्यादा जुल्म अपनी ही कमुनिटी के लोगों पर किया है।''

अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी को लेकर सफाई देते रहे अखिलेश, मंच से कही ये 5 बड़ी बात

आगरा.समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार को आगरा में हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव को पार्टी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश अपनी स्पीच में नेताजी को लेकर सफाई देते नजर आए।

अखिलेश ने कहा- नेताजी ने हम सबको फोन पर आशीर्वाद दिया है।

अखिलेश ने कही ये 5 बड़ी बातें

1.हमाने नेताजी से कहा था, सम्मेलन में आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कल भी बात हुई। इस सम्मेलन में आने से पहले भी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि संविधान में संशोधन होने जा रहे हैं। नेताजी ने हम सबको फोन पर आशीर्वाद दिया है।

2.बीजेपी से बड़ा उनका झूठ है। वो पहाड़ जैसा है।

3. इस सरकार से किसान, व्यापारी नौजवान सब परेशान हैं।

4.जीएसटी से उद्योग बंद हो गए।

5. नोट बंदी से पूरे देश का व्यापार संकट में आ गया।

बिहार

टैंकर की चपेट में आने से रिटायर्ड फौजी की मौत, ऐसे तेल लूटते रहे लोग

मुजफ्फरपुर. एनएच-28 पर दिघरा पेट्रोल पंप के पास बुधवार की दोपहर करीब दो बजे तेल टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार रिटायर्ड फौजी महावीर प्रसाद की मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल है जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा तेल टैंकर व मालवाहक टाटा-407 के ओवरटेक के दौरान हुआ। जिसकी वजह से दोनों के वाहन चालकों ने नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर फरार हैं। आक्रोश में लोगों ने एनएच पर काफी देर तक हंगामा किया।

महावीर मनियारी थाने के सोनबरसा पंचायत के मोहम्मदपुर आलम गांव के निवासी हैं। वह अतरदह में काम निबटाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना हुई। इसकी जानकारी जैसे ही मृतक के परिजनों को लगी वह मौके पर पहुंचे और तेल टैंकर चालक की लापरवाही को मौत की वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने पुलिस को भी शव उठाने से मना किया। स्थिति बिगड़ती देख सदर थानेदार ने मामले की सूचना डीएसपी आशीष आनंद को दी। एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, डीसीएलआर पूर्वी शाहजहां, ब्रह्मपुरा थानेदार उपेंद्र सिंह, मनियारी थाना, मुशहरी सीओ नागेंद्र कुमार, विधायक केदार गुप्ता व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को शांत कराया।

3 क्रेन से उठाया गया टैंकर

सीओ नागेंद्र कुमार ने मृतक के परिजन को पारिवारिक लाभ योजना के तहत बीस हजार का चेक दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। टैंकर पलटने के बाद आग लगने की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया था और आसपास एनएच पर पानी का छिड़काव हुआ। टैंकर को उठाने के लिए तीन क्रेन भी लगाए गए थे।

एनएच पर तीन घंटे बंद रहा वाहनों का परिचालन

हादसे के बाद दोनों गाड़ी पलटने से एनएच पर तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इससे यात्रियों को परेशानी हुई और घटना स्थल के दोनों ओर एक से दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। फिर शाम करीब पांच बजे से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।

लोगों में गुस्सा, अतिक्रमण के कारण हुई दुर्घटना

स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने बताया कि एनएच के किनारे तेल और गैस टैंकर समेत कई बड़े वाहन दिन-रात खड़े रहते हैं। इससे बाइक समेत छोटे वाहनों को साइड लेने में परेशानी होती है।

ट्रेन की चपेट में आने से पारा मेडिकल छात्रा के कटे दोनों पैर, स्थिति गंभीर

दलसिंहसराय.समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड के दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन स्थित फुट ओवरब्रिज के पास गुरुवार को पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से पारा मेडिकल की छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस दौरान छात्रा का दोनों पैर व एक हाथ की सभी उंगलियां कट गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ व जीआरपी ने मिलकर स्थानीय लोगों और रिक्शा चालक की मदद से उसे उठाकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने छात्रा की प्राथमिक उपचार करते हुए उसे गंभीर स्थित में पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। घायल छात्रा की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शाखमोहन पंचायत अंतर्गत झौहर गांव निवासी सुभाष कुमार की पुत्री कविता कुमारी (22 वर्ष) के रूप में की गई।

गैंगरेप की घटना दबाने को 500 रुपए में सौदा तय करने वाले 3 पंचों के घर की होगी कुर्की

मुजफ्फरपुर/कटरा.कटरा गैंग रेप मामले को दबाने के लिए नवादा गांव में पंचायती कर 500 रुपए में सौदा तय करने वाले तीनों फरार पंचों के घर की कुर्की होगी। पुलिस इसकी कवायद में जुट गई है। कटरा थानेदार रतन कुमार ने बताया कि पंचायती में मामले को दबाने का प्रयास करने वाले नवादा के सौरभ कुमार, रविशेखर और बीर विक्रम सिंह उर्फ गब्बर के विरुद्ध शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट से कुर्की का आदेश लिया जाएगा। गैंग रेप को अंजाम देने वाले चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद भी नामजद किए गए तीनों लगातार गांव में दिखते रहे। इन तीनों के इशारे पर उस खेत को भी जोता गया, जिसमें किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के साथ ही हाजिर होने के लिए सामाजिक दबाव भी डलवाया। लेकिन, तीनों हाजिर नहीं हो रहे। इसको देखते हुए पुलिस अब इनके घर की कुर्की का आदेश कोर्ट से मांगेगी। इसके अलावा पंचायती में शामिल छह अन्य लोगों का नाम भी सामने आया है जिन्होंने आरोपितों का पक्ष लिया था। इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में पुष्टि होने के बाद इनकी भी गिरफ्तारी होगी।

पंच ने चारों आरोपितों को किया था बेनकाब

दूसरे गांव की होने के कारण पीड़िता गैंगरेप को अंजाम देने वाले आरोपितों का नाम नहीं जानती थी। घटना के अगले दिन जब उसने परिजनों को रेप की बात बताई, जिसके बाद बात गांव में फैल गई। तब पंच लालबाबू ने ही चारों आरोपित युवकों को सामने लाया। उन्होंने घटना की शाम किशोरी के पीछे चारों आरोपितों को देखा था। पंचायती के जरिए मामले को दबाने के प्रयास की जानकारी भी लालबाबू और उपसरपंच ने पुलिस तक पहुंचाई थी ।कटरा गैंगरेप की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है।

दो स्पेस एजेंसी ने किया आकलन, 20 हजार प्रति हेक्टेयर मिलेगा फसल बीमा

मुजफ्फरपुर.नासा व यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से अब बाढ़ से हुई फसल की बर्बादी का आकलन किया जाएगा। सेटेलाइट डाटा की मदद से फसल क्षति का आकलन कर बाढ़ बीमा योजना के लिए मुआवजा भी निर्धारित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गायघाट प्रखंड के छह गांवों के 200 किसानों को इस साल से बाढ़ बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान 1 नवंबर के बाद यहां के किसानों को 20-20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा का भुगतान करेगा। गायघाट के बेनीबाद के पास बागमती नदी में लगे संयत्र की मदद से प्राप्त डाटा के आधार पर फसलों की क्षति का आकलन किया गया है। इस साल आई बाढ़ में 200 में से 180 हेक्टेयर में लगी फसल को पूरी तरह बर्बाद बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की ओर से जून माह में गायघाट प्रखंड के छह गांव के 200 किसानों का प्रीमियम जमा किया गया था। 10 साल बाद बागमती नदी में आई बाढ़ से इस साल फसलों की व्यापक क्षति हुई। लिहाजा, इन सभी गांव के बीमित किसान बाढ़ फसल बीमा से लाभान्वित होंगे। संस्थान के अनुज कुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अधिक होने व खेत में कितनी अवधि तक कितना पानी जमा होने के आधार पर किसानों को बाढ़ फसल बीमा का लाभ मिलेगा। अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों के नाम पर प्रति हेक्टेयर 9.5 फीसदी व कम बाढ़ प्रभावित इलाके के किसानों के नाम पर से 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा की गई है।

बिहार में अपराधियों की सेवा में जुटी पुलिस, साथ में करती है भोजन और मार्केटिंग

मधुबनी/पटना. अपराधियों का बिहार में हर दिन खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर इसपर अंकुश लगाने की बात करते हैं। इधर, उनके जवानों के कैदियों से आवभगत का मामला सामने आया है। ये मामला मधुबनी से जुड़ा हुआ है।

बिहार पुलिस कैदियों की आवभगत को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है।

प्रदेश में कोई बड़ी घटना होने पर ऐसे मामले ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं।

पुलिस इससे हमेशा इंकार करती रही है।

गुरुवार को पुलिस और अपराधी की सांठ गांठ की एक तस्वीर फिर सामने आयी।

इस बार ये तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले से आई है।

फोटो में पुलिस कैदियों को शॉपिंग करवाते दिख रही है।

मामला यहीं नहीं रुका पुलिस के जवान कैदी को लेकर होटल में खाना खाने भी पहुंच गए।

बिहार पुलिस के जवान मधुबनी मंडल कारा से कैदियों को कोर्ट में पेशी के बाद लेकर बाजार चले गए।

ये सब पुलिस के जवान कुछ पैसा लेकर करते हैं।

इसके बाद कैदी पुलिस सुरक्षा में ही अपने मनमाफिक खरीददारी कर सकता है।

अपने परिवारवालों के साथ होटल में चाय-नाश्ता, खाना खा सकता है।

स्कूल टीचर ने बच्चों के साथ किया अप्राकृतिक यौनाचार, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

सुपौल. बिहार के सुपौल में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने छोटे-छोटे बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। मामला त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लिटिल एवेंजर बोर्डिंग स्कूल से जुड़ा है। घटना दशहरे की छुट्टी से पहले की है। छुट्टी के बाद जब पैरेंट्स बच्चों को लेकर स्कूल लाए तब इस मामले का खुलासा हुआ। आरोपी शिक्षक शिव शंकर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के लिटिल एवेंजर बोर्डिंग स्कूल में आस-पास के गांव के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। विजयादशमी की छुट्टी के मौके पर जब बच्चे अपने घर गए तो टीचर की हरकत अपने मां बाप को बताया।

प्रिंसिपल ने की मामले को दबाने की कोशिश

स्कूल खुलने पर अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के बारे में प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने पहले मामला को रफा-दफा करने की कोशिश की। इससे बच्चों के परिजन आक्रोशित हो गए और त्रिवेणीगंज थाना में आवेदन दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

पीएम के स्वच्छता अभियान को लगा झटका, शौचालय बने स्टोर रूम

अहमदाबाद। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए देशवासियों को आगे आने का आह्वान किया था। स्वच्छता अभियान के तहत जगह-जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। इसके विपरीत गांधीनगर में मंत्रियों के आवास से कुछ ही दूर बोरीज गांव के हालात बहुत ही अलग हैं। यहां सरकार द्वारा बनाए गए शौचालयों का उपयोग स्टोर रूम की तरह होता है। सरकार ने यहां शौचालय बनवा तो दिए, पर शौचालयों को गटर से नहीं जोड़ा गया। इससे अब उसका उपयोग स्टोर रूम की तरह किया जा रहा है। कुछ लोगों ने शौचालयों पर ताला लगा दिया है।

शौचालय केवल दिखावा

गांधीनगर के अक्षरधाम के सामने स्थित बोरीज गांव में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि गांव की सारी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो वास्तविकता का अहसास हो जाता है। यहां सभी जाति के लोग रहते हैं। सरकार ने जल्दबाजी में शौचालय तो बनवा दिए, पर उसे गटर से नहीं जोड़ा गया। इससे तंग आकर कई लोगों ने खुद ही वहां पर गड्ढे खोदकर शौचालय शुरू कर दिए। कुछ इलाकों में लोगों ने खुद ही आगे आकर शौचालय को गटर से जोड़ दिया।

गटर से जोड़ना ही भूल गई सरकार

यहां गांव में आधे दर्जन से अधिक शौचालय बनाए गए। पर जल्दबाजी में इसे गटर से जोड़ना भूल गई। इसलिए 6 महीने से कुछ शौचालय बंद पड़े हैं। कुछ भी ताला लगा दिया गया है और कुछ लोग उसका उपयोग स्टोर रूम की तरह कर रहे हैं।

सब स्टेशन पर चढ़ा युवक धू-धू कर जलता रहा, लोग बनाते रहे वीडियो

राजकोट। शहर के गोकुलनगर मेन रोड पर स्थित सम्राट इंडस्ट्रीज के पास सब स्टेशन पर मानसिक रूप से अस्थिर युवक चढ़ गया। जैसे ही उसका शरीर हाईवोल्टेज पावर से छू गया, वैसे ही वह धू-धू कर जलने लगा। बाद में वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब यह घटना घट रही थी, तब स्थानीय लोग मोबाइल से इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे थे।

क्रिकेटर जडेजा के रेस्त्रां पर छापा, मिलीं बासी सब्जियां, थमाया नोटिस

राजकोट। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा के रेस्त्रां पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा, जहां उसे बासी सब्जियां मिली। ये चीजें फ्रिज में रखी हुई थी। इस पर रेस्त्रां को नोटिस दिया गया है। त्योहार करीब आते ही सक्रिय होता है स्वास्थ्य विभाग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर के कालावड रोड के करीब क्रिकेटर रवींद्र जडेजा का जड्डुस फूड्स फील्ड नाम का रेस्त्रां है। इसे उनकी बहन नैना अनिरूद्ध सिंह जडेजा चलाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के छापे के दौरान पकी हुई सब्जी और अन्य चीजें जैसे- मंचूरियन, नूडल्स, पास्ता आदि फ्रिज में रखी मिली थी। इसके अलावा पके हुए चावल, दाल फ्राय, उबले हुए आलू भी फ्रिज में रखे हुए थे। लोगों का मानना है कि त्योहार के करीब आते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो जाता है और प्रसिद्धि पाने के लिए सेलिब्रिटी को अपना शिकार बनाता है।

सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विट से गुजरात की राजनीति में मचा हड़कम्प

अहमदाबाद। गुजरात में कांग्रेस-भाजपा द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी अपना दम-खम दिखाने के लिए मैदान में आने को तैयार हैं। इस बार का चुनाव निर्णायक होगा, इसके पूरे आसार है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि गुजरात में आनंदी बेन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विट में आनंदीबेन पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा है कि केवल वे ही भाजपा को जीत दिला सकती हैं। उधर गुजरात में विकास के नाम पर सत्ता विरोधी सुर सुनाई देने लगे हैं। विकास के नाम पर रोज नए जोक्स सामने आ रहे हैं। ऐसे में विकास पागल हो गया है, मेसेज ने भाजपा की नींद हराम कर दी है। इसमें भाजपा घिर गई है। इसे साफ करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को गुजरात आना पड़ रहा है। भाजपा की गौरव यात्रा को सफलता नहीं मिली, इससे भी पार्टी की फजीहत ही हुई है।

अमित शाह की पहली पसंद रूपाणी ही हैं

अमित शाह पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व में शाह ने 150 से अधिक सीटें जीतेन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में स्वामी का ट्विट किसी नए समीकरण की ओर इशारा करता है। उनके ट्विट ने गुजरात भाजपा में गरमाहट ला दी है।

हाल ही में अमित शाह आनंदीबेन के घर जाकर मिले थे

गुजरात विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भाजपा का प्रचार बूमरेंग साबित हो रहा है। अब चुनावी बागडोर आनंदी बेन संभालेंगी, ऐसी चर्चाओं का जोर है। गुजरात में भाजपा की जीत के लिए हाईकमान ने आनंदीबेन का नेतृत्व स्वीकारने के लिए कह दिया है। इसी के चलते पिछले एक पखवाड़े में भाजपा की जितनी भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, उसमें आनंदीबेन उपस्थित रहीं। अमित शाह ने भी पिछले दिनों उनके घर जाकर भेंट की। वे उनसे लगातार सम्पर्क में भी हैं।

एक बार फिर बेन को बनाने की चर्चा

यह सच है कि अपनी आयु को लेकर आनंदीबेन से स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद अमित शाह का बयान आया कि 75 साल से अधिक आयु के व्यक्ति भी भाजपा में चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा द्वारा तय की गई समय सीमा रद्द होते ही आनंदीबेन पुन: सक्रिय हो गई हैं। इसमें उन्होंने घाटलोडिया से ही विधानसभा चुनाव लडने् के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि केवल विधायक बनने के लिए ही वे चुनाव नहीं लड़ रहीं हैं, बल्कि वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद को तैयार कर रहीं हैं।

रूपाणी की विफलता को ढांकने का प्रयास

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया था। इस दो वर्षों के दौरान गुजरात में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन हुए। इसके बाद भी आनंदीबेन ने अपनी सूझबूझ से आंदोलन खत्म करने और भाजपा की छबि न बिगड़े, इसके लिए पूरी कोशिश की थी। इस दौरान एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने महिलाओं, बच्चों और युवाओं लिए अनेक नीति विषयक निर्णय लिए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तो भाजपा की छवि धीरे-धीरे खराब होने लगी। प्रजा का विश्वास खोने लगी। पिछले 6 महीनों में विजय रूपाणी के खिलाफ प्रजा का रोष कई बार देखा गया।

बेन की रणनीति महत्वपूर्ण

विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे विजय रूपाणी के खिलाफ सत्ता विरोधी ज्वाला अधिक तेज होने लगी है। इस आग को बुझाने के प्रयास में अमित शाह समेत भाजपा के कई अन्य राष्ट्रीय नेता गुजरात में आने लगे हैं।

इसके बाद भी लोगों का रोष कम नहीं हो रहा है। इसलिए एक बार फिर गुजरात भाजपा को बचाने के लिए आनंदी बेन का सहारा लिया जा रहा है। इसकी यही वजह है कि अपने दो साल के कार्यकाल में आनंदी बेन ने चुनावी रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस समय पाटीदार आंदोलन तेज से तेजतर होता जा रहा है। पाटीदारों का सबसे अधिक विरोध अमित शाह के खिलाफ देखने को मिल रहा है। आनंदी बेन के मैदान में आने से पाटीदारों को मनाने के प्रयास होंगे। पाटीदार आंदोलन के समय बेन के खिलाफ भारी रोष था।

आनंदीबेन के इस्तीफे के बाद रूपाणी सरकार में पाटीदारों के साथ हुई वार्ता में पाटीदार अच्छी तरह से समझ गए कि इससे तो अच्छी हमारी पाटीदार बहन आनंदीबेन थीं।

गुंजा हेलिपेड से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो, रविवार को आएंगे वडनगर

वडनगर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अपने गांव वडनगर आ रहे हैं। इस दौरान गुंजा हेलिपेड से मोदी का रोड शो आयोजित होगा। बुधवार को गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने अधिकारियों के साथ स्थल की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज का उदघाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभा संबोधित करेंगे।

गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी रविवार को अपने गांव वड़नगर आ रहे हैं। प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि रविवार को सुबह गुंजा हेलिपेड से मोदी का भव्य रोड शो आयोजित होगा। वहां से हाटकेश्वर महादेव, स्कूल रेलवे स्टेशन वाले रास्ते से होते हुए 600 करोड़ के खर्च से बने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उदघाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वड़नगर के सभी घरों और रास्तों को रोशनी से सजाया जाएगा। इसके अलावा जगह-जगह मोदी के कट आउट लगाए जाएंगे।

गृह राज्य मंत्री के साथ-साथ डीजीपी गीता जौहरी, आईजी शिवानंद झा, कलेक्टर एचएम पटेल, एसपी चैतन्य मांडलिक, केएल रबारी, सोमाभाई मोदी, पुलिस प्रमुख सोनियाबेन पटेल सहित अधिकारी मौजूद रहे।

भरूच की सभा में दो लाख की भीड़ जुटाने का प्रयास

रविवार को भरूच में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा सभा में दो लाख की भीड़ जुटाने के प्रयास में जुट गई है। भरूच में भाड़भूत के नजदीक नर्मदा नदी पर बनने वाले बैरेज का प्रधानमंत्री मोदी भूमिपूजन करेंगे। भूमिपूजन के बाद सभा संबोधित करेंगे। सभा में लाखों की भीड़ जुटाने के लिए सूरत, भरूच, नर्मदा और वडोदरा से लोगों को लाया जाएगा। भरूच के भाजपा जिलाध्यक्ष योगेश पटेल ने बताया कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए गांवों में बैठक की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात आ रहे हैं। भरूच में विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की लंबी लाइन है।

भरूच, अंकलेश्वर, वागरा, झगडिया और जंबूसर सीट पर टिकट दावेदारों के लिए शक्ति प्रदर्शन करने का यह अच्छा मौका है।

कांग्रेस विधायक को पहनाई जूतों की माला

अहमदाबाद। शहर के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ग्यासुद्दीन शेख को रैली के दौरान एक शख्स ने जूतों की माला पहना दीकांग्रेस विधायक को जूतों की माला पहनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अहमदाबाद के दरियापुर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन शेख का अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोग फूलों की माला से स्वागत कर रहे थेफूलों की माला से स्वागत के बीच एक शख्स जूतों की माला लेकर ग्यासुद्दीन शेख करीब पहुंच गया और उनके गले में जूतों की माला डाल दीअपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किरकिरी सहमे ग्यासुद्दीन खामोशी से इस घटना को बर्दास्त कर गए।

वाघेला ने कांग्रेस को चेताया, कहा चिट्ठा निकालूंगा तो होगी तकलीफ

गांधीनगर। जन विकल्प की घोषणा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जन विकल्प के नाम से पार्टी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

जल्द ही इसकी घोषणा होगी। हालांकि वाघेला बार-बार कह रहे हैं कि वे पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को अंकलेश्वर के पास काफिले में हुए बवाल को लेकर नाराज वाघेला ने ट्वीट करके कांग्रेस को चेतावनी दी है।

कांग्रेस समझ जाए, तो ही बेहतर

वाघेला ने कहा कि कांग्रेस समझ जाए तो अच्छा है नहीं तो प्रमाण के साथ चिट्ठा निकालने पर बहुत तकलीफ होगी।

हालांकि कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है पर सूत्रों का कहना है कि वाघेला की चेतावनी कांग्रेस नहीं बल्कि अहमद पटेल के लिए है।

शंकरसिंह वाघेला 6 अक्टूबर से अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, वडोदरा में 'फेस टू फेस' के नाम से जनता और समर्थकों से सीधे संवाद करने जा रहे हैं।

भाजपा के 22 साल में जनता को फायदा नहीं

वाघेला का कहना है कि प्रदेश के सभी शहरों और जिलों से असंख्य लोगों के संदेश आ रहे हैं। कांग्रेस का कुछ ठिकाना नहीं है और भाजपा के 22 साल में जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए फेस टू फेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

गुलबर्ग केस : गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की

अहमदाबाद (ईएमएस)गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में दाखिल की गई जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया है। जाकिया जाफरी ने गुलबर्ग हत्याकांड केस में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य को दी गई क्लीन चिट को अदालत में चुनौती दी थी। जाकिया ने याचिका में मांग की थी कि वर्ष 2002 के गुलबर्ग हत्याकांड में 59 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी और इसमें किसी बड़ी साजिश के आरोप को मानने से भी इंकार कर दियागुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया से कहा है कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं। हाईकोर्ट के न्यायधीश ने दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश के आरोपों के संबंध में मोदी और अन्य लोगों को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को सही ठहराया।

गोंडल के निलेश हत्या केस में भाजपा विधायक समेत तीन को जमानत मिली

अहमदाबाद (ईएमएस)सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट जिले के गोंडल में निलेश रैयाणी हत्या केस में भाजपा विधायक समेत तीन आरोपियों को आज जमानत दे दी13 साल पुराने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थीहाईकोर्ट के फैसले को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थीसुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 30 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया थासुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जयराजसिंह जाडेजा समेत तीनों आरोपियों ने गत 28 सितंबर को गोंडल की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया थाजहां से तीनों को गोंडल सब जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज निलेश रैयाणी हत्या केस में जयराजसिंह जाडेजा, अमरजीतसिंह जाडेजा और महेन्द्रसिंह राणा को गुजरात में प्रवेश नहीं करने, पासपोर्ट जमा करने और 5-5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दीसुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद की जाएगीनिलेश रैयाणी हत्या केस में गोंडल के सत्र न्यायालय ने भाजपा विधायक जयराजसिंह जाडेजा, अमरजीतसिंह जाडेजा और महेन्द्रसिंह राणा को निर्दोष घोषित किया थाजबकि समीर शिराजखान पठान को उम्रकैद की सजा सुनाई थीगोंडल सत्र न्यायालय के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई की सजा का आदेश दिया था हाईकोर्ट के फैसले को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थीसुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सर्व प्रथम आत्म समर्पण करने का आदेश देते हुए मामले पर सुनवाई 3 अक्टूबर मुकर्रर की थी लेकिन किन्हीं कारणों से 3 अक्टूबर को सुनवाई नहीं हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने जयराजसिंह समेत तीनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दीसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही तीनों आरोपी जेल से रिहा जाएंगेरिहाई के बाद तीनों आरोपियों को गुजरात से बाहर जाना होगा। गौरतलब है वर्ष 2004 में वाछरा गांव निवासी नीलेश मोहनभाई रैयाणी, जयेश साटोडिया और रामजी मारकणा यूटिलिटी जीप में गोंडल के बालिका छात्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे ।

विकास का उपहार करनेवाली कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी : रूपाणी

अहमदाबाद (ईएमएस)मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि विकास का उपहास करनेवाली कांग्रेस को जनता कभी माफ नहीं करेगीकांग्रेस के लिए विकास उपहास है, जबकि भाजपा के लिए विकास मिजाज हैविकास अब और तेज व आक्रामक हो गया है तथा भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है, जिसे देख कांग्रेस बौखला गई है गुजरात गौरव यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विजय रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद में यकीन करती है, जबकि भाजपा राष्ट्रवाद को तवज्जो देती हैकांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतु वाघाणी ने कहा कि भाजपा ने पिछले दो दशक में सबका साथ सबका रुपए का तुरंत प्रावधान कर समाज के सभी वर्गों को साथ रखने का प्रशंसनीय प्रयास किया हैपाटीदार आंदोलन के दौरान पुलिस दमन संबंधी मामलों की जांच के लिए कहा कि आनेवाले दिनों में अनारक्षति वर्ग की 58 जातियों को शैक्षकि और आर्थिक उपार्जन के अवसर मिलेंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com